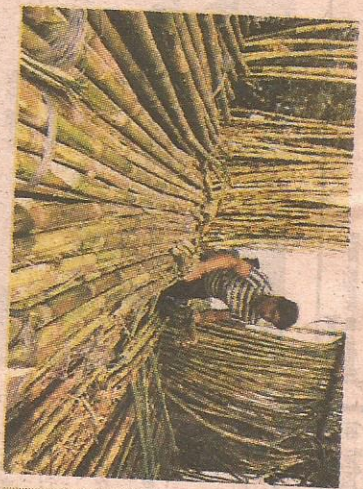


# गान्ना रिकवरी का होगा तकनीकी ऑडिट

बीएस संवाददाता  
लखनऊ, 29 अक्टूबर



**उत्तर प्रदेश सरकार की योजना।**  
राज्य के मुख्य सचिव जे.पेरार्ड सत्र 2014-15 के लिए राज्य परामर्श मूल्य निर्धारण से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की।  
गान्ना किसानों को लाभ दिलाने के लिए रिकवरी तथा उत्पादकता बढ़ाई जाए।  
गान्ना किसानों एवं चीनी मिलों के हितों को देखते हुए पेरार्ड का कार्य जल्द शुरू कराया जाए।

चीनी मिलों की कमजोर गान्ना रिकवरी की शिकायत को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरार्ड सत्र के दौरान तकनीकी ऑडिट कराने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि गान्ना किसानों एवं चीनी मिलों के हितों को देखते हुए पेरार्ड का कार्य जल्द शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गान्ना उत्पादकता एवं रिकवरी को और अधिक बढ़ाए जाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जाए ताकि किसानों एवं चीनी मिल मालिकों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों का भाविष्य गान्ने पर निर्भर करता है इसलिए गान्ना किसानों एवं चीनी मिलों के हितों को ध्यान में रखते हुए गान्ना मूल्य का निर्धारण यथाशीघ्र तय किया जाए। उन्होंने कहा कि चीनी मिल मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों के गान्ने के मूल्य का भुगतान समय से प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि गान्ना

मूल्य तय करते समय यह अवश्य ध्यान दिया जाएगा कि चीनी मिल मालिकों का नुकसान न होने पाए लेकिन गान्ना किसानों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों में रिकवरी पर होने वाले नुकसान का तकनीकी ऑडिट भी कराए जाने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।  
मुख्य सचिव पेरार्ड सत्र 2014-15 के लिए राज्य परामर्श मूल्य निर्धारण से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है

लेकिन चीनी मिलों के संचालन में आने वाली बाधाओं को भी प्राथमिकता से दूर कराया जाए। उन्होंने कहा कि गान्ना किसानों की बेहतर किसान के गान्ने का वाजिब मूल्य अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को चीनी मिल मालिकों के माध्यम से प्राप्त होने वाली सस्मिडी उनकी मांग पर सीधे उपलब्ध कराए जाने पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि गान्ना किसानों को लाभ दिलाने के लिए रिकवरी तथा उत्पादकता बढ़ाई जाए। प्रमुख सचिव, गान्ना विकास गठित भटनगर ने कहा कि गान्ना मूल्य के

निर्धारण के लिए गान्ना किसानों एवं चीनी मिल मालिकों द्वारा दिए गए आकलन पर निर्णय लेने के लिए गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मशा है कि किसानों के हित के साथ-साथ चीनी मिल मालिकों का भी नुकसान न होने पाए।  
बैठक में चीनी मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों, गान्ना किसान प्रतिनिधियों, खांडसारी यूनिट के प्रतिनिधियों सहित फेडरेशन एवं गान्ना वैज्ञानिकों ने भी गान्ना मूल्य निर्धारण के लिए अपनी राय व्यक्त की।